13-02-2023 TITLE: Re: Delay in setting up of Kaushal Vikas Kendra in Delhi and issue of widening of road. SPECIAL MENTION (ZERO HOUR) Bidhuri, Shri Ramesh Skill Development Skill Development Centre

TITLE: Re: Delay in setting up of Kaushal Vikas Kendra in Delhi and issue of widening of road.

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली): माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से दिल्ली में एक सोई हुई राज्य सरकार की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । जनता के हित में कुछ योजनाएं बनाकर निर्णय लिए गए थे । 148ए राजमार्ग से जौनापुर मांडी रोड के चौड़ीकरण एवं उसी मार्ग पर सिंगापुर विश्वस्तरीय कौशल केन्द्र को राजनीतिक विद्वेष के कारण लटका दिया गया है । अब उन्हें निरस्त करने का भी प्रयास दिल्ली सरकार द्वारा किया जा रहा है ।

उस मार्ग पर लगभग 5 गांवों की आबादी 5 गुना बढ़ गई है और उसी रफ्तार से यातायात भी बढ़ रहा है। उस मार्ग का चौड़ीकरण करना था, वहां प्रतिदिन हजारों लोग भीषण जाम की समस्या से जूझते हैं। राज्य सरकार पीडब्ल्यूडी द्वारा योजना के तहत उक्त मार्ग को चौड़ा करना था। वर्ष 2012 में यह प्रोजेक्ट 597 करोड़ रुपये में 9 किलोमीटर लम्बा बनाया जाना था। राज्य की जमीन अधिकृत करने की प्रक्रिया भी शुरू हुई थी, लेकिन रसूखदार लोगों के दबाव में आकर इसे रोक दिया गया।

जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी कौशल विकास के लिए पूरे देश के अंदर अलग-अलग केन्द्र खोलने का प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में नौजवानों के कौशल को निखार कर उन्हें रोजगार देने के साथ अन्य को रोजगार देने का भी प्रयास हुआ है। देश में इसी प्रकार कि केन्द्र सरकार स्थापित कर रही है।

दिल्ली की केजरीवाल सरकार उक्त कौशल विकास केन्द्र को लटकाये हुए है, जबकि इस कौशल केन्द्र को 2 जुलाई, 2012 में दिल्ली सरकार के मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी। उस समय शीला दीक्षित जी की सरकार थी। 18 सितम्बर, 2012 को राजस्व एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने इसे पीडब्ल्यूडी को सौंप दिया था।

24 दिसम्बर, 2014 को शहरी विकास मंत्री ने भूमि के भू प्रयोग को चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से परिवर्तित कर दिया था, जब दिल्ली में राष्ट्रपति शासन था। इसे शहरी विकास मंत्री जी ने कराया था। उसके बाद 30 करोड़ 28 लाख रुपये ग्राम सभा जौनापुर खाते में जमा भी कर दिए गए थे।

उसके बाद मार्च, 2015 में लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने सरकार पर दबाव बनाकर 2 करोड़ 74 लाख रुपये स्वीकृत भी किए। मार्च, 2017 में भवन निर्माण हेतु 254 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए ।

सभापति महोदय, वर्ष 2012 से 2023 आ गया और 12 वर्ष बीत गए। लोगों के हित में और युवाओं के भविष्य से जुड़ी इन योजनाओं, चाहे कौशल विकास केन्द्र हो या जौनापुर मार्ग को 100 फुट चौड़ीकरण करके फरीदाबाद से जोड़ना हो, इन सभी कार्यों को लटकाया जा रहा है।

मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि केन्द्र सरकार राज्य सरकार पर दबाव बनाए वरना ऐसी राज्य सरकार को बर्खास्त करे जो जनता के हित में काम नहीं कर पाती है ताकि ये काम पूरे किए जा सकें। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।